गणतंत्र दिवस - 2018

के अवसर पर

श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

संदेश

भोपाल : 26 जनवरी, 2018

आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बुजुर्गों एवं प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों

गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएँ। आज के दिन देश ने हमारे संविधान को अंगीकृत कर नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा का वचन दिया था। देश ने राजनैतिक, नागरिक स्वतंत्रता का लम्बा सफर तय किया है। आज समानता और सामाजिक, आर्थिक न्याय के क्षेत्र में देश का कोई सानी नहीं है। हमने विकास और प्रगति के नये कीर्तिमान बनाये हैं। अब हमारा लक्ष्य अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना है।

मध्यप्रदेश देश के नाड़ी तंत्र का केन्द्र है। प्रदेश में प्रकृति, इतिहास और संस्कृति की बहुरंगी सम्पदाएँ बिखरी पड़ी हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल, ताप्ती, वेत्रवती जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ हैं। देश में प्रकृति ने हीरा जैसा बहुमूल्य खनिज केवल मध्यप्रदेश को दिया है। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। द्वादश ज्योर्तिलिंगों में से दो महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्यप्रदेश में ही हैं। साँची, खजुराहो, भीमबेटका के रूप में प्रदेश के पास तीन विश्व धरोहर हैं। मध्यप्रदेश ने सच्चे अर्थों में अपनी बहुवर्णीय सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत में देश की बहुलता, विविधता और सबसे बढ़कर समरसता को आत्मसात किया है। देश की रक्षा में प्रदेश के वीर सपूतों की गौरवशाली परम्परा रही है। प्रदेश की जन-वत्सला धरती को आज के पावन दिन मैं प्रणाम करती हूँ।

मध्यप्रदेश जिस मुकाम पर है वह प्रदेश की जनता और सरकार के एकसाथ खड़े होने से संभव हुआ है। मुझे विश्वास है कि हमारी आगे की यात्रा समृद्ध और सुखद होगी।

आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हैं और विकास दर पिछले एक दशक से दो अंकों के करीब रही है, कृषि विकास दर तो 18 से 20 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष हो रही है। प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ पार कर चुका है और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत जहाँ प्रदेश में 5.50 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक एक रूपये प्रति किलो अनाज के माध्यम से पहुँचा गया है, वहीं शहरों में दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को 5 रूपये थाली भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रत्येक गरीब को छत मिले इस हेतु मध्यप्रदेश ने कानून बनाकर इसे सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर रहने वाले 27 लाख ग्रामीणों को अभी तक भू-अधिकार पत्र दिया गया है। सभी पात्र बेघर परिवारों को आवास के लिये भू-खण्ड उपलब्ध हो जाए इस उद्देश्य से आज से पूरे प्रदेश में भू-खण्ड अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरूआत की है। यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश में योजना के तहत लगभग 31 लाख परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी एक वर्ष में 30 लाख परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा।

नि:शक्तजन, वृद्धजन, निराश्रितों, कन्याओं एवं विधवा, परित्यक्ताओं के लिये अनेक जन-कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। सिंगल क्लिक से 36 लाख पेंशनरों के खातों में प्रतिमाह एक तारीख को रू. 116 करोड़ की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। किसी भी महिला के विधवा होने पर जो विपत्ति उस पर आती है, उससे तात्कालिक रूप से निपटने के लिए पेंशन योजना का लाभ में गरीबी रेखा का बंधन हटाने का निर्णय सरकार ले रही है। केवल उन्हीं को इसकी पात्रता नहीं होगी जो शासकीय कर्मचारी हैं या स्वयं आयकर दाता हैं।

समुदाय को शिक्षा से जोड़ने के लिये "मिल बाँचें मध्यप्रदेश" कार्यक्रम प्रदेश की 1 लाख से अधिक शालाओं में चलाया गया जिससे जनता की भागीदारी बेहतर हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों का विस्तार बड़े पैमाने पर किया गया है।

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक, छात्रवृत्ति, सिला हुआ गणवेश और साईकिल जैसी सुविधाएँ राज्य व्दारा प्रदान की जा रही हैं। 12 वीं कक्षा में अधिक अंक लाने वाले लगभग 19 हजार छात्र और छात्राओं को कम्प्यूटर खरीदने के लिये 25 हजार रूपये दिये गये।

प्रदेश के गरीब मेधावी बच्चे जो 12 वीं के बाद व्यावसायिक अथवा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में धनराशि के अभाव में नहीं पढ़ पाते थे उनके लिये राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसमें उनकी स्नातक शिक्षा की फीस सरकार वहन कर रही है। पहले ही वर्ष में इस योजना के

तहत 28 हजार से ज्यादा बच्चों को स्नातक शिक्षा के लिये लाभ दिया गया है।

प्रदेश में स्कूली शिक्षा में पढ़ाने वालों की कई श्रेणियाँ बन गई थीं जैसे शिक्षक, अध्यापक, गुरूजी आदि। इस कारण अध्यापन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए राज्य शासन पढ़ाने वालों की केवल एक श्रेणी ही बनाने जा रही है

ग़रीबों तक उच्च शिक्षा को पहुँचाने हेतु इसके विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में पिछले वर्ष 15 नये तथा 03 नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना के साथ पूर्व से संचालित 23 कॉलेजों में नवीन संकाय/विषय एवं कुल 11 स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ की गई हैं। विद्यार्थियो को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य शासन प्रदेश के एक विश्वविद्यालय को देश के 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों में लाने हेतु विशेष प्रयास करेगा।

बाल मृत्यु दर में पिछले एक वर्ष में सर्वाधिक 10 अंकों की कमी मध्यप्रदेश में रिकार्ड हुई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई इंद्रधनुष योजना में टीकाकरण की दर 74% से बढ़कर 90% हुई है। प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर के रोगियों को नि:शुल्क कीमोथेरेपी उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी 51 जिलों में नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

साढ़े 20 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि से हजारों मरीजों को ईलाज के लिये मदद दी जा रही है। आगामी 8 मार्च से 30 मई तक पुन: यह शिविर लगाए जाएंगे।

चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 7 नये मेडिकल कॉलेज प्रांरभ किये जा रहे हैं तथा पूर्व से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि की जा रही है। प्रदेश के प्रथम बोन मेरी ट्रांसप्लांट की स्थापना इंदौर मेडिकल कॉलेज में की गई है।

राज्य सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या अधिक है, उन्हें चिन्हित कर क्षेत्र विशेष के लिए योजनाएँ लाई जा रही हैं। विशिष्ट रूप से पिछड़ी जनजातियाँ बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक हजार रूपये प्रतिमाह का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा रहा है जिससे वे बच्चों के लिए पोषण आहार खरीद सकें। सुपोषण अभियान और स्नेह सरोकार कार्यक्रम आँगनवाड़ियों में चलाए जा रहे हैं। अति कुपोषित 85 विकासखण्डों में साढ़े ग्यारह लाख स्कूली बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गुड़-मूंगफली की चिक्की देने की योजना लागू की जा रही है।

टेकहोम राशन की वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब टेकहोम राशन की तैयारी कंपनियों के व्दारा करने के स्थान पर महिला स्व-सहायता समूहों के जिला स्तरीय संघ व्दारा की जायेगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और लक्ष्य समूहों तक लाभ बेहतर ढंग से पहुँचेगा।

प्रधानमंत्रीजी द्वारा प्रारम्भ स्वच्छ भारत मिशन में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश के 13 जिले और 10 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। चार साल पहले करीब 33 लाख घरों की तुलना में आज 81 लाख से भी अधिक घरों में शौचालय सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 450 से ज्यादा सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाये जा रहे हैं। मैं प्रदेश के जन-मानस से अपील करना चाहूँगी कि वे इस मिशन में अपनी सक्रिय भागीदारी देने के लिए आगे आएं।

राज्य के सभी शहर खुले में शौच मुक्त शहर घोषित हो गये हैं। सभी नगरीय निकायों के लिये निजी-जन भागीदारी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एजेंसी मार्च 2018 तक नियुक्त कर दी जायेंगी।

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी ग्रामों को चरणबद्ध तरीके से नल-जल योजनाओं के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। समूह नल-जल योजनाओं के जरिए हम लगभग 5 हजार गाँवों की 56 लाख आबादी तक पहुँच जाएँगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत एक हजार तक की आबादी वाले गाँवों को नल-जल योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सभी नगरीय निकायों की पेयजल आवर्द्धन परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं।

गरीबों को रोजगार मिले इस हेतु कौशल संवर्धन आवश्यक है। राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण मिशन के नाम से एक नया मिशन प्रारंभ किया है, जिसके तहत हर साल 7.50 लाख

युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जायेगा और इतने ही युवाओं को रोजगार अथवा स्व-रोजगार से प्रति वर्ष जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार भोपाल में एशियन विकास बैंक की मदद से विश्व स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना करने जा रही है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन से सवा 23 लाख से ज्यादा परिवारों को दो लाख से ज्यादा स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। मिशन द्वारा सवा छह लाख बेरोजगारों को रोजगार और साढ़े चौदह लाख परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक लाख 6 हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को रोजगार/ स्व-रोजगार में लगाया गया है।

प्रदेश में अभूतपूर्व नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गयी, जिसमें बड़ी संख्या में समाजसेवियों, धार्मिक अनुयायियों और आम जनता के लोगों ने भाग लिया। नदी संरक्षण का संदेश देने वाला यह अभूतपूर्व अभियान जनता की सक्रिय भागीदारी के कारण सफल हो पाया। इस संरक्षण अभियान को मूर्तरूप देने के लिए नर्मदा सेवा मिशन के नाम से परियोजना तैयार की गयी है। इसके तहत 2 जुलाई को नर्मदा कछार में 6 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये हैं। नदी के तटों पर साढे 4 हजार शांतिधाम बनाये गये हैं और ढाई सौ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण किए जा रहे हैं। पाँच घाटों पर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिन उद्योगों का पानी नदी

में जाता था उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

हाल ही में सांस्कृतिक एकता के देवदूत, अद्वैत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता एवं सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के एकात्म दर्शन को जन-जन तक पहुँचाने एवं ओंकारेश्वर में उनकी 108 फीट की अष्ट धातु प्रतिमा की स्थापना के लिये प्रतीकात्मक धातु संग्रहण करने के उद्देश्य से "एकात्म यात्रा" निकाली गयी। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊँची अष्टधातु प्रतिमा की स्थापना का 22 जनवरी को शिलान्यास हो गया है। सरकार ने आदिगुरू शंकराचार्य की स्मृति और प्रेरणा में सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन किया है ।

प्रदेश ने पिछले चौदह साल में कृषि के क्षेत्र में हर पैमाने पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसमें किसानों की अनथक मेहनत भी उतनी ही परिणामकारी रही है, जितनी राज्य सरकार की नीतियाँ और फैसले। प्रदेश को लगातार पाँचवें वर्ष भी कृषि कर्मण अवार्ड दिये जाने की घोषणा हो चुकी है। विगत चार वर्ष में 18 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत कृषि विकास दर प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है।

प्रदेश ने देश में सबसे पहले किसानों की आय पाँच वर्षों में दोगुना करने का रोड-मैप बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए फसल भावांतर योजना प्रारंभ की है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सोयाबीन, उडद, मूंग, मूंगफली और मक्का आदि फसलों में मिल पाया है। योजना के तहत दिसम्बर तक लगभग बारह

लाख किसानों को लगभग 1500 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है और अनेक राज्य इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। किसान भाइयों के प्रयासों से उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा अभी 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में 1300 करोड़ रुपये के निवेश अनुबंध किये गये हैं।

प्रदेश अब दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा है। पिछले वर्ष दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 10.70 प्रतिशत रही, जो देश की वृद्धि दर से दोगुनी है। प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्र के 90 प्रतिशत में मछली पालन हो रहा है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण के लिये 58 हजार मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके हैं।

किसानों के लिए खेती का खर्च कम हो, इस हेतु राज्य सरकार ने शून्य ब्याज दर का लाभ दिया है, जिससे प्रदेश के लगभग 17 लाख किसान लाभांवित हुए है। सरकार ऐसे किसान, जो मजबूरीवश सहकारी बैंकों में डिफाल्टर हो गये हैं, को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा पुन: बहाल करने के लिए शीघ्र ऋण समाधान योजना लाने जा रही है।

प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य हुआ है। अत्यंत कठिन से दिखने वाले कार्य जैसे नर्मदा का पानी क्षिप्रा में डालकर सिंचाई, पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग बनाकर पानी ले जाना को भी सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर पूरा किया। साढ़े सात लाख हेक्टेयर सिंचित रकबे से बढ़ाते हुए सिंचाई की क्षमता वर्ष 2025 तक शासकीय स्त्रोतों से 60 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। इस वर्ष अब तक करीब 25 हजार हेक्टेयर

क्षमता की 65 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। नर्मदा-पार्वती और नर्मदा-कालीसिंध नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रदेश आज बिजली के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर है, बल्कि हम सरप्लस बिजली बेचते हैं। सभी कृषि उपभोक्ताओं को 10 घन्टे और अन्य उपभोक्ताओं को 24 घन्टे बिजली देने का काम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्रीजी द्वारा चलायी गयी सौभाग्य योजना के तहत 2018 तक प्रदेश के हर घर में बिजली पहुँचाने का सरकार का लक्ष्य है जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में बदलने हेतु "मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना" प्रारंभ की गयी है। जून **2019** तक ऐसे 5 लाख अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कर दिया जायेगा।

प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क सुधारने के व्यापक प्रयास किये गये हैं। लगभग तीन हजार कि.मी. के नये राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर किये जा चुके हैं तथा 2 हजार 383 कि.मी. नये राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पौने तीन हजार कि.मी. नये राज्य राजमार्ग और सवा चार हजार कि.मी. लम्बाई के नये मुख्य जिला मार्ग घोषित किये गये हैं। तीन हजार कि.मी. लम्बाई के मुख्य जिला मार्गों का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं से अब तक 75 हजार कि.मी. से ज्यादा लम्बाई की सड़कों का निर्माण हो चुका है।

प्रदेश के सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की हमारी योजना है। जो गाँव अभी तक पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी में इसी वर्ष कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

इस प्रकार प्रदेश का कोई भी गाँव पहुँच विहीन नहीं रह जाएगा।

प्रदेश के सात शहर भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना में स्मार्ट सिटी विकास की कार्यवाही प्रचलन में है। एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहर एवं पर्यटन शहर ओंकारेश्वर में अमृत योजना में पाँच वर्षों में 6 हजार 200 करोड़ की राशि व्यय की जायेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास के लिए एक पंचवर्षीय एकीकृत कार्य-योजना तैयार की जा रही है। कार्य- योजना के जरिए इन परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण के कार्य सुनियोजित ढंग से चलाए जाएंगे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आबादी से अधिक राशि राज्य आयोजना में रखी जा रही है। करीब ढाई लाख वन अधिकार-पत्र बाँटे जा चुके हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को रोजगार, स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं से विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं तीन अन्य शहर, जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड/ तहसील मुख्यालय पर कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आवास किराया दिया जा रहा है।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये सभी जिलों में 100 सीटर बालक और 50 सीटर बालिका छात्रावास बनाये गये हैं। इन्दौर में पाँच सौ और शाजापुर में पचास सीटर बालिका छात्रावास का कार्य पूर्ण होने को है। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ साढ़े 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला है। मुख्यमंत्री स्व-

रोजगार योजना में इस वर्ष पन्द्रह सौ से ज्यादा हितग्राहियों को करीब 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है।

अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु कौशल विकास, स्व-रोजगार और छात्रवृत्ति की योजनाएँ प्रदेश में संचालित हैं। भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के लिये करीब डेढ़ लाख प्रकरण भेजे गये हैं। भोपाल में हज हाउस बन गया है। वक्फ संपत्ति का कम्प्यूटरीकरण जारी है।

प्रदेश की महिला सशक्तीकरण की कोशिशें देश में मिसाल बनी हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 27 लाख बालिकाओं को मिल चुका है। प्रत्येक बालिका को वयस्क होने पर 1 लाख 18 हजार रूपये प्राप्त होंगे। शौर्या दल निचले स्तर पर महिला अनुकूल वातावरण बनाने में सफल रहे है। लाडो अभियान से 83 हजार बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है।

प्रदेश पिछले वर्षों में निवेशकों की पहली पसंद बना है। राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई नीति लेकर आई है जिसमें प्रदेश में नवीन रूप से स्थापित होने वाली इकाइयों को पूँजीगत अनुदान की व्यवस्था की गई है। निवेशकों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट पोर्टल बनाया जा रहा है, जो उनके प्रस्ताव और उसके पूरे जीवन चक्र की मानिटरिंग करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश को वर्ष 2015 और 16 में पाँचवीं रैंक मिली है। प्रदेश में रुपये 2300 करोड़ की लागत से 22 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य इस वर्ष पूरा हो जायेगा।

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना इसी अप्रैल से प्रभावशील हो जायेगी। इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर तक करीब सवा 10 हजार करोड़ की लागत के डेढ़ लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का उद्योग आधार मेमोरण्डम में पंजीयन हुआ। इन इकाइयों से साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अधिकतम परियोजना लागत एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। किसान पुत्र/ पुत्री को रुपये 2 करोड़ तक के नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये पूँजी उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना प्रारम्भ की गई है। पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुद्रा योजना के तहत 6 लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में औद्योगिक शांति की आदर्श स्थिति है। श्रम विभाग की 32 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाकर केन्द्रीकृत पोर्टल से सिंगल विण्डो से सुलभ करवाया जा रहा है। करीब 26 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर 312 करोड़ से ज्यादा के हितलाभ दिये जा चुके हैं। पब्लिक स्कूल की तर्ज पर इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित श्रमोदय विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र से श्रमिकों के 3200 बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।

सुशासन राज्य सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। समय सीमा में नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने की कानूनी गारंटी के बाद राज्य सरकार अब इससे एक कदम आगे जा

रही है और "समाधान एक दिन" लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

पिछले वर्ष से अब तक करीब साढ़े ग्यारह लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राजस्व महाअभियान में 10 लाख अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे निराकृत हुए हैं। किसानों को सवा 4 करोड़ खसरा एवं खतौनी नकल नि:शुल्क बाँटी गई हैं।

सरकार के प्रयासों का सुफल है कि प्रदेश पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन रहा है। अब जिला स्तर पर धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास की योजना है। हनुवंतिया की तर्ज पर ओंकारेश्वर के नजदीक सैलानी टापू को जल-पर्यटन के केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। कुल 15 जलक्षेत्रों पर जल-पर्यटन केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। इस वर्ष गांधीसागर में जल महोत्सव की शुरूआत की जा रही है।

उज्जैन, जबलपुर एवं ग्वालियर में बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक कला-संकुल स्थापित किये गये हैं। भोपाल में भारत माता की प्रतिमा और वीर भारत परिसर के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में नई रेत उत्खनन नीति सरकार व्दारा बनाई गई है। नीति के तहत आगामी फरवरी माह से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी रेत खदानें चालू हो जाएंगी जहाँ से कोई भी नागरिक पंचायत को रायल्टी का भुगतान कर रेत उत्खनन कर सकेगा। सड़कों पर रेत भरे वाहनों की चेंकिंग बन्द की जाएगी।

यह गर्व की बात है कि देश के कुल वनक्षेत्र का बारह प्रतिशत से ज्यादा हमारे प्रदेश में है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की प्रभावी पहल का ही परिणाम है कि वनों और उन पर आश्रित ग्रामीणों की स्थिति में सुधार हुआ है। इस वर्ष आठ करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है।

इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरणपादुका योजना प्रारंभ की गई है जिसमें संग्राहकों को जूता/चप्पल एवं पानी की बॉटल तथा महिला संग्राहकों को इनके अतिरिक्त साड़ी दी जाएगी। इससे 21 लाख से अधिक संग्राहक लाभान्वित होंगे। सरकार ने महुआ फूल, महुआ गुल्ली तथा अचार गुठली का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है ।

भौतिक प्रगति के पैमाने से आगे बढ़कर राज्य सरकार ने देश में पहली बार आनंद विभाग की स्थापना की है। पचास हजार लोग स्वेच्छा से आनंदक बने हैं। शासकीय सेवकों में सकारात्मक सोच के विकास के लिये 780 अल्पविराम कार्यक्रम किये गये। आनंदम गतिविधि में 172 स्थानों पर अतिरिक्त सामान को छोड़ने तथा उस सामान की जिसे जरूरत हो, वहाँ से नि:शुल्क तथा बिना किसी से पूछे ले जाने की व्यवस्था संचालित है। इस माह ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आनंद उत्सव मनाया गया।

मध्यप्रदेश कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमेशा अच्छे राज्यों में गिना जाता रहा है। सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस बलों में वृद्धि के विशेष प्रयास किए हैं। पुलिस थाने और पुलिस चौकियों की संख्या में वृद्धि की गई है।

महिला अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस वर्ष विशेष कानून पारित किया है जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून राज्य में तत्काल लागू हो जाएगा। प्रदेश पुलिस की डायल-100 योजना को सत्रह दूसरे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश लागू कर रहे हैं।

कर्मचारियों के कल्याण पर राज्य शासन ने हमेशा ध्यान दिया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राज्य शासन ने नियमित किया है। अध्यापक संवर्ग को छठे वेतनमान का लाभ दिया गया है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की वेतन वृद्धियाँ की गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पुलिस कर्मियों के लिए अगले पाँच साल में 25 हजार नए मकान बनाए जाएंगे।

आईये आज के दिन हम प्रण करे कि ईमानदारी से अपने कार्यक्षेत्र के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और एक ऐसे समरस प्रदेश के निर्माण में अपने को समर्पित करेंगे, जिसमें सबको रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और रोजगार की सुविधा मिलेगी।

जय-हिन्द।

जय-मध्यप्रदेश।

पद्म सम्मानों की घोषणा

केन्द्र सरकार ने पद्म सम्मानों की घोषणा की है। कुल 85 लोंगों को यह सम्मान दिया जाएगा। इनमें मध्यप्रदेश की चार हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें लिटरेचर और एजुकेशन के लिए भोपाल की श्रीमती मालती जोशी और उज्जैन के साहित्यकार श्री के. मुसलगांवकर, आर्ट एंड पेंटिंग के लिए पाटनगढ़ (डिंडोरी) के श्री भज्जू श्याम व आर्ट क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए बाबा श्री योगेंद्र को पद्मश्री दिया जाएगा।

मैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किये जाने वाली मध्यप्रदेश की इन चारों हस्तियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है।

देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर और देश के अन्य सभी महापुरूषों को मैं प्रणाम करती हूँ।

आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बुजुर्गों एवं प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों